To Double the income of the Farmers

715. Shri Varun Choudhry, M.L.A.: Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be pleased to state the steps taken by the Government to double the income of the farmers in the State togetherwith the input and outcome thereof?

JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

Sir,

The Agriculture & Farmers Welfare Department, Haryana implementing various schemes/programs to uplift the income of the farmers in the state towards achieving the objective of doubling the income of farmers. The steps taken by the department to increase the income of farmers are: -

1. Rs. 6000 per year cash incentive is being given to all farmers in the State through Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN).

2. State declared the Sugarcane price at Rs. 362/- per quintal, which is the highest in the country. During the 2020-21, an amount of Rs. 329 Crores was provided to various sugar mills of the state as subsidy for payment of sugarcane price to sugarcane growing farmers.

3. Bajra was covered under *Bhavantar Bharpayee Yojana* (BBY) during Kharif 2021. Rs. 600/- per quintal as difference of the MSP and average market price (i.e. between Rs. 2250 and Rs. 1650) was paid to the farmers.

4. Government of India announced Agriculture Infrastructure Fund (AIF) during last FY 2020-21 to develop agriculture infrastructure like godown, packhouse and all other post harvesting structures etc.

5. *"सेम एवं कल्लर भूमि सुधार योजना"* has been launched by the department for participation of farmers in the scheme for treatment of alkaline and saline soil.

6. **Uttam Beej Portal** has been launched for Govt./private agencies to register their seed growers at this portal from Rabi 2021-22.

7. State Government decide to procure pulses and oilseeds (Sunflower, Gram, Groundnut, Arhar, Til, Urad) when the market price fell below the MSP.

8. The farmers were given incentive @ Rs. 7000/-per acre for replacing paddy (water guzzling crop) with alternate crops (less water consuming) like Cotton, Bajra, Kh. Pulses, Maize, Horticulture/ Vegetables.

9. To promote Pulses (Moong, Arhar and Urad) and Oilseeds crops (Castor, Groundnut and Til) in place of Bajra in the State. Financial assistance of Rs. 4,000 per acre has been given to the farmer.

10. Financial assistance is being given @ Rs. 5000 per acre to a farmer for setting up the demonstration plots of Direct Seeded Rice (max. upto 2.5 acres).

11. State Government cover the risk of farmer's crops through Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Similarly, Mukhya Mantri Bagwani Yojana also provide the risk coverage to horticultural crops.

12. A total of 19052 CRM machines i.e. 8842 individual category machines on 50% subsidy and 10210 machines in 2551 CHCs with 80% subsidy have been provided to the farmers.

13. Department of Horticulture has launched a unique Crop Cluster Development Program and would be first State to establish complete supply chain for fresh fruits and vegetables. In each cluster one FPO is being formed with 300 farmer members. Further, in each cluster one integrated pack house is being established for supply chain, marketing of horticulture produces and linking of farmers directly with the market.

14. Haryana is in forefront of formation of Farmer Producer Organizations (FPOs) in the country.

15. Haryana is the first State to establish a Honey Trade Centre (HTC) at Integrated Beekeeping Development Center (IBDC), Ramnagar, Kurukshetra.

16. Horticulture Department is promoting innovative technologies as vertical farming to enhance yield, increase availability and thereby doubling the income of farmers.

17. CCSHAU, Hisar became the First Agriculture University among SAUs of the Country having 07 Community Radio Stations for the welfare of the farmers. Farmers will be provided latest information related to improved varieties of crops as well as their sowing information, diseases and pests and solutions, weather information, advice of university scientists, animal husbandry and home science.

किसानों की आय दोगुना करना

715. श्री वरुण चौधरी, एम०एल०ए० : क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं तथा इनकी आय तथा व्यय क्या है ?

जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

महोदय,

किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कृषि और किसान कल्याण विभाग, हरियाणा राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। किसानों की आय बढ़ाने हेतू विभाग द्वारा उठाए गए कदमः–

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम–किसान) के माध्यम से राज्य के सभी किसानों को 6000 रूपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन रा ि दी जा रही है।

2. राज्य ने गन्ने का मूल्य 362/– रूपए प्रति क्विंटल घोशित किया है, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य की विभिन्न चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए वर्श 2020–21 के दौरान सब्सिडी के रूप में 329 करोड़ रूपए की रा ि प्रदान की गई।

3. खरीफ 2021 के दौरान बाजरे को भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) के तहत कवर किया गया था। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और औसत बाजार भाव (यानी 2250 रूपए और 1650 रुपए के बीच) के अंतर के रूप में 600/– रूपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया।

4. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कृषि बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए जैसे गोदाम, पैकहाउस और अन्य सभी पोस्ट हार्वेस्टिंग संरचनाओं आदि हेतू कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) की घोषणा की गई।

5. विभाग द्वारा क्षारीय एवं लवणीय मृदा उपचार योजना में किसानों की भागीदारी हेतू **''सेम एवं कल्लर भूमि सुधार योजना''** प्रारम्भ की गई है।

6. रबी 2021–22 से बीज उत्पादकों को पंजीकृत करने के लिए सरकारी/निजी एजेंसियों के लिए उत्तम बीज पोर्टल प्रारम्भ किया गया है।

7. राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार भाव कम होने पर दालों और तिलहनों (सूरजमुखी, चना, मूंगफली, अरहर, तिल, उड़द) की खरीद का फैसला लिया है।

8. फसल धान (अधिक पानी की खपत वाली फसल) के स्थान पर कम पानी की खपत वाली फसलें कपास, बाजरा, खरीफ दालें, मक्का, बागवानी/सब्जियों जैसी वैकल्पिक फसलों को अपनाने वाले किसानों को 7000/–रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन दिया गया।

9. राज्य में बाजरा के स्थान पर दलहनी फसलें (मूंग, अरहर व उड़द) और तिलहनी फसलें (अरंडी, मूंगफली व तिल) को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 4000/– रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी गई है।

10. धान की सीधी बिजाई (अधिकतम 2.5 एकड़ तक) के लिए के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतू किसान को 5000/– रूपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

11. राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की फसलों के जोखिम को कवर करती है। इसी तरह मुख्यमंत्री बागवानी योजना भी बागवानी फसलों को जोखिम कवरेज प्रदान करती है।

12. किसानों को कुल 19052 फसल अव ोश मशीनें जिनमें से 8842 म ीने 50 प्रति ात सब्सिडी व्यक्तिगत स्तर पर और 2551 कस्टम हायरिंग सैन्टर में 10210 मशीनें 80 प्रति ात सब्सिडी के साथ प्रदान की गई हैं।

13. बागवानी विभाग ने एक अनूठा फसल समूह विकास कार्यक्रम शुरू किया है और ताजे फल और सब्जियों के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला पहला राज्य होगा। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफपीओ का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला, बागवानी उत्पादों के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस स्थापित किया जा रहा है।

14. हरियाणा देश में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन में सबसे आगे है।

15. एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी), रामनगर, कुरुक्षेत्र में हनी ट्रेड सेंटर (एचटीसी) स्थापित करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।

16. बागवानी विभाग उपज बढ़ाने, उपलब्धता बढ़ाने और इस तरह किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ऊर्ध्वाधर खेती के रूप में नवीन तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है।

17. चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृशि वि वविद्यालय, हिसार किसानों के कल्याण हेतू 07 सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ कृशि वि वविद्यालयों में दे ा का पहला राज्य कृशि विश्वविद्यालय बन गया। किसानों को फसलों की उन्नत किस्मों के साथ–साथ उनकी बुवाई की जानकारी, रोगों, कीटों और समाधान, मौसम की जानकारी, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सलाह, पशुपालन और गृह विज्ञान से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान की जाएगी।